भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2755

उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर और भारतीय संस्थानों के विदेशी परिसर

2755 **श्री मिलिंद मुरली देवरा:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विनियम, 2023 के अंतर्गत उन विदेशी विश्वविद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिन्होंने महाराष्ट्र सहित देश में अपने परिसर स्थापित किए हैं या जिन्हें परिसर स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ है;

(ख) आईआईटी और आईआईएम सहित उन भारतीय संस्थानों की संख्या कितनी है जिनके विदेशों में परिसर हैं तथा उनमें नामांकन की स्थिति तथा परिणाम क्या रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में कमी लाने के संबंध में इन पहलों के प्रभाव का आकलन किया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की वर्ष-वार संख्या कितनी है तथा इन उपायों के लागू होने के बाद से इस संबंध में क्या प्रवृत्तियां रही हैं; और

(ङ) महाराष्ट्र सहित देश में उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अंतर्गत प्रस्तावित अन्य कदम क्या हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ड़): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एफएचईआई) को 16 आशय पत्र (एलओआई) जारी किए हैं। यूजीसी ने कर्नाटक में छह, महाराष्ट्र में छह, दिल्ली एनसीआर में तीन और तमिलनाडु में एक एफएचईआई को एलओआई जारी किए हैं। महाराष्ट्र में छह आशय पत्रों में से चार एफएचईआई (यॉर्क विश्वविद्यालय, ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, एबरडीन विश्वविद्यालय और इलिनोइस प्रौद्योगिकी संस्थान) को मुंबई में शैक्षणिक प्रचालन शुरू करने के लिए अनुमोदन पत्र

दिया गया है। साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय ने पहले ही क्रमशः गुरुग्राम और बेंगलुरु में अपने परिसर स्थापित कर लिए हैं।

आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद ने वर्ष 2023 में ज़ांज़ीबार, वर्ष 2024 में अबू धाबी और वर्ष 2025 में दुबई में अपने विदेशी परिसर स्थापित किए हैं। आईआईएम अहमदाबाद ने सितंबर 2025 में दुबई परिसर में एक वर्ष का पूर्णकालिक एमबीए प्रोग्राम शुरू किया, साथ ही मध्य-पूर्व, एशिया और अफ्रीका के व्यावसायिकों के लिए जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया। इस कार्यक्रम में 35 छात्र हैं। आईआईटी मद्रास ने वर्ष 2023 में ज़ांज़ीबार में अपना परिसर खोला, अब तक 35 छात्रों ने डेटा साइंस तथा कृत्रिम मेधा और महासागर संरचनाओं में एमटेक की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। 100 से अधिक छात्र डेटा साइंस और केमिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग में विभिन्न बीएस कार्यक्रमों में हैं। आईआईटी दिल्ली ने वर्ष 2024 में आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में नौ यूजी, पीजी और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के साथ अपना अपतटीय परिसर स्थापित किया। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में परिसर में 171 छात्र थे।

विदेश में अध्ययन व्यक्तिगत इच्छा और पसंद का मामला है, जो विभिन्न कारकों पर निर्भर है, जिसमें सामर्थ्य, वित्त तक पहुंच, विदेशी समाजों के संपर्क और अध्ययन की विशेष शाखा के लिए योग्यता शामिल है। गृह मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (बीओआई) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021 से 2025 तक विदेश जाने के दौरान अध्ययन/शिक्षा के रूप में अपनी यात्रा का उद्देश्य बताने वाले भारतीयों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	2021	2022	2023	2024	2025
विद्यार्थियों की संख्या	445580	752100	894758	760060	619264

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) सहित भारत सरकार ने उच्चतर शिक्षा में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें की हैं, जिसमें सार्वजनिक वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे का उन्नयन, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के मानदंडों को पूरा करने वाले नए संस्थानों और पाठ्यक्रमों की मान्यता, अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देना और पहुंच के लिए डिजिटल पहल को बढ़ाना शामिल है। इन पहलों ने संस्थानों के एक व्यापक पूल में योगदान दिया है और देश में शैक्षिक सुविधाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करने में भी योगदान दिया है।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता सहित कई पहल की हैं, जिसमें संयुक्त/दोहरी/युग्मित डिग्री कार्यक्रमों के लिए विनियम जारी करना, इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम के लिए दिशानिर्देश, उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठों की

स्थापना, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की अवधारणा को बढ़ावा देना, अभिगम्यता दिशानिर्देश और उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए मानक, एनईपी 2020 की उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए उत्साह पोर्टल (उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी कार्यनीतियां और कार्रवाई करना) की शुरुआत, जीवन कौशल पर पाठ्यक्रम तथा दिशानिर्देश जारी करना 2.0, संकायों के निरंतर क्षमता निर्माण के लिए मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी) का शुभारंभ शामिल हैं।

समग्र परिणाम के रूप में, 52 भारतीय संस्थान अब क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (क्यूएस डब्ल्यूयूआर) 2027 में हैं, जो भारत का अब तक का सबसे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है, यह क्यूएस डब्ल्यूयूआर 2015 में 11 भारतीय संस्थानों की तुलना में वृद्धि को दर्शाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक (2025) के अनुसार भारत का वैश्विक स्तर पर 38वें स्थान है। भारत को पैमाने, वित्तपोषण और यूनिकॉर्न काउंट के आधार पर विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र (शीर्ष 3) में से एक माना जाता है।

इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में आकर्षित करने के लिए, मंत्रालय ने वर्ष 2018 में 'स्टडी इन इंडिया' योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य भारत को सस्ती लागत पर विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग स्टडी इन इंडिया (एसआईआई) पोर्टल है, जो सभी आने वाले विदेशी छात्रों के लिए प्रवेश और वीजा आवेदनों के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन है और भारतीय उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।

देश में 1,289 विश्वविद्यालय, 48,246 कॉलेज और 15,221 स्टैंड-अलोन संस्थान हैं, जिनमें से 87 विश्वविद्यालय, 5,380 कॉलेज और 2,426 स्टैंड-अलोन संस्थान महाराष्ट्र में स्थित हैं। उच्चतर शिक्षा में छात्र नामांकन के मामले में महाराष्ट्र लगभग 46.53 लाख छात्रों के साथ देश के शीर्ष सात राज्यों में से एक है। महाराष्ट्र में उच्चतर शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटल एकीकरण, गुणवत्तापूर्ण प्रत्यायन, ऑनलाइन अधिगम, संस्थागत अभिशासन तथा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी), ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (एपीएएआर), स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयम), समर्थ एवं पीएम विद्यालक्ष्मी जैसी पहलों के जरिए वित्तीय सहायता के माध्यम से काफी सुदृढ़ किया गया है।

सरकार ने जून 2023 में प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 12,926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) का तीसरा चरण शुरू किया है, जिसमें शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रूसा के पूर्व चरणों की प्रतिबद्ध देनदारियां भी शामिल हैं। महाराष्ट्र राज्य में, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत, योजना के विभिन्न घटकों के तहत 1431.31 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सेदारी: 863.37 करोड़ रुपये) की अनुमोदित राशि के साथ कुल 144 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

*****